4 फरवरी 2026
बुधवार

केशव टाइम्स
डिजिटल संस्करण

धान अधिप्राप्ति में बक्सर ने पकड़ी रफ्तार, लेकिन लक्ष्य अभी दूर 2

एक नजर

कोलकाता में महसूस किए गए भूकंप के झटके 5.9 आंकी गई तीव्रता

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता मंगलवार (3 फरवरी) रात को भूकंप के झटके महसूस किए गए. जिससे लोगों में दहशत फैल गई और वो अपने घरों और इमारतों से बाहर निकल आए. रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.9 आंकी गई है. इस भूकंप का केंद्र पड़ोसी देश म्यांमार बताया जा रहा है. अधिकारियों के अनुसार भूकंप से किसी तरह की कोई जान-माल की हानि या संपत्ति को नुकसान की कोई खबर नहीं आई है. हालांकि भूकंप के झटकों ने लोगों में कुछ देर के लिए दहशत में डाल दिया था. अधिकारियों ने बताया कि म्यांमार में आए तेज भूकंप के बाद मंगलवार को कोलकाता और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में झटके महसूस किए गए. इसके साथ ही बांग्लादेश में भी तेज झटके महसूस किए गए.भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर लगभग 5.9 मापी गई है

मुंबई एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला, एअर इंडिया और इंडिगो विमान के विंग्स की टक्कर

मुंबई। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उस समय हड़कंप मच गया जब एअर इंडिया और इंडिगो एयरलाइंस के दो विमानों के पंख आपस में टकरा गए. यह घटना ग्राउंड मूवमेंट के दौरान हुई.जानकारी के अनुसार, एअर इंडिया का विमान उड़ान के लिए पुशबैक प्रक्रिया में था. जबकि इंडिगो का विमान लैंडिंग के बाद टैक्सी कर रहा था. इसी दौरान दोनों विमानों के पंखों में टक्कर हो गई. सबसे अहम बात यह रही कि हादसे के समय दोनों विमानों में यात्री सवार थे. हालांकि, राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी यात्री या क्रू मेंबर के घायल होने की खबर नहीं है. घटना के बाद संबंधित अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों विमानों को रोक दिया और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की.एयरपोर्ट प्रशासन और एयरलाइंस की तकनीकी टीम ने जांच शुरू कर दी है. फिलहाल यह पता लगाया जा रहा है कि एटीसी निर्देशों में चूक, ग्राउंड हैंडलिंग की गलती या तकनीकी कारण से यह टक्कर हुई।

बिहार सरकार ने पेश किया 3.47 लाख करोड़ का बजट

बिहार बजट 2026

विभाग	2025-26 बजट (₹ करोड़)	2026-27 बजट (₹ करोड़)
शिक्षा एवं उच्च शिक्षा	—	68,216.95
ग्रामीण विकास	—	23,701.18
स्वास्थ्य विभाग	20,035.80	21,270.40
गृह विभाग (पुलिस–प्रशासन)	17,831.21	20,132.87
ऊर्जा विभाग	—	18,737.06
सड़क निर्माण (ग्रामीण + शहरी)	6,806.53 (पथ निर्माण)	18,716.97
नगर विकास एवं आवास	11,982.26	(सड़क मद में समाहित)
कृषि विभाग	3,528.22	(कल्याणकारी/ग्रामीण मद में समायोजन)
उद्योग विभाग	1,966.26	—
आपदा प्रबंधन	4,967.35	—
पर्यटन विभाग	1,103.91	—
कल्याणकारी विभाग (कुल)	5,409.57 (SC+EB-C+OBC)	13,202.38
अनुसूचित जाति (SC)	1,839.11	19,603.02
अनुसूचित जनजाति (ST)	—	1,648.42
कला, संस्कृति एवं युवा	277.19	—
खेल विभाग	248.39	—
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन	906.29	

एजेंसी। पटना

बिहार सरकार ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2026-27 का बजट विधानसभा में पेश किया, जिसमें कुल आकार 3,47,589.78 करोड़ रुपये रखा गया है। राज्य सरकार का दावा है कि बिहार तेजी से प्रगति कर रहा है और चालू वित्त वर्ष में वृद्धि दर 14.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने बजट पेश करते हुए केंद्र की ओर से बिहार को मिली उदार सहायता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दूरदर्शी नेतृत्व की भी सराहना की, जो समावेशी विकास पर केंद्रित है। मंत्री ने सदन को बताया, 'वर्ष 2026-27 के लिए बजट का आकार 3,47,589.78 करोड़ रुपये है, जो 2025-26 के 3,16,895.02 करोड़ रुपये की तुलना में 30,694.74 करोड़ रुपये अधिक है। राजकोषीय घाटा लगभग 39,400 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 2.99 प्रतिशत है।'उन्होंने कहा, 'इस सदन की ओर से मैं प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिनके नेतृत्व में देश निरंतर प्रगति कर रहा है। पिछले वर्ष के केंद्रीय बजट में बिहार को कई सौगातें मिलीं, जिनमें नए हवाई अड्डे, मखाना बोर्ड और अन्य खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां शामिल हैं। राज्य सबसे तेजी से विकसित होने वाले राज्यों में रहा है और 2024-25 में इसकी वृद्धि दर लगभग 14.9 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। हमें आशा है कि शीघ्र ही हम देश के शीर्ष राज्यों में शामिल होंगे।

किसानों और कलाकारों को मिलेगी आर्थिक मदद

सरकार ने उन वरिष्ठ कलाकारों के लिए जो अब कमजोर और आर्थिक रूप से तंगी में हैं, एक नई योजना शुरू की है। इसके तहत पात्र कलाकारों को हर महीने 3,000 रुपये पेंशन दी जाएगी ताकि वे आराम से और सम्मान के साथ अपना जीवन जी सकें। किसान भाइयों के लिए भी सरकार ने नई मदद की योजना जननायक कपूर्री ठाकुर किसान सम्मान निधि बनाई है। इस योजना के तहत किसानों को साल में 3,000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे, ठीक वैसे ही जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलती है। सरकार ने आने वाले वर्षों में एक करोड़ नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व की तारीफ

जदयू नेता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ईमान, ज्ञान, विज्ञान, अरमान और सम्मान इन पांच तत्वों का प्रतीक बताया, जो विकसित बिहार की दिशा में समावेशी प्रगति और न्याय के साथ विकास सुनिश्चित कर रहे हैं। मंत्री ने महिला सशक्तीकरण पर मुख्यमंत्री के विशेष जोर की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि हाल में शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना इसका ताजा उदाहरण है। इस योजना के तहत कुल 1.56 करोड़ महिलाओं को 10,000-10,000 रुपये दिए गए हैं। जिन्होंने इस राशि का उपयोग व्यवसाय शुरू करने में किया है, उन्हें शीघ्र ही दो लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता मिलेगी।

वित्तीय स्थिति और विकास लक्ष्य

बजट में राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत बताया गया है। इसमें कहा गया है कि 2024-25 में राजस्व घाटा जीएसडीपी का केवल 0.04 प्रतिशत रहा, जबकि राजकोषीय घाटा 4.16 प्रतिशत रहा, जो निर्धारित 3.0 प्रतिशत की सीमा से अधिक है। मंत्री ने बताया कि सरकार ने अगले पांच साल में राज्य की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। तेज औद्योगिक विकास के लिए पांच लाख करोड़ रुपये का निजी निवेश आकर्षित करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। वर्ष 2026-27 में राज्य की अपनी राजस्व प्राप्तियां 75,202.98 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जिसमें कर राजस्व का हिस्सा 65,800 करोड़ रुपये होगा।

बंगाल में एसआईआर के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, सीएम ममता के मौजूद रहने की संभावना

एजेंसी। कोलकाता

सुप्रीम कोर्ट बुधवार को पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई करेगा। इस अहम सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खुद अदालत में मौजूद रहने की भी संभावना जताई जा रही है।सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार, इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी, जिसमें न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली भी शामिल होंगे। पीठ ममता बनर्जी, मोस्तारी बानो तथा तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रायन और डोला सेन द्वारा दायर याचिकाओं समेत याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई करेगी। सूत्रों के मुताबिक, एलएलबी की डिग्री रखने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद भी अदालत में मौजूद रहकर अपनी दलीलें रख सकती हैं। इससे पहले 19 जनवरी को शीर्ष अदालत ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कई निर्देश जारी किए थे। अदालत ने कहा था कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए और इससे आम लोगों को किसी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि 'लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी' सूची में शामिल मतदाताओं के नाम ग्राम पंचायत भवनों और प्रखंड कार्यालयों में प्रदर्शित किए जाएं, जहां दस्तावेज और आपत्तियां भी जमा की जा सकें।

क्या है लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी!

लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी में वर्ष 2002 की मतदाता सूची से संबंधित वंशानुक्रम जोड़ने में विसंगतियां शामिल हैं, जिनमें माता-पिता के नाम में अंतर या मतदाता और उनके अभिभावक के बीच आयु का अंतर 15 वर्ष से कम या 50 वर्ष से अधिक होना शामिल है। मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने यह भी कहा था कि राज्य में करीब 1.25 करोड़ मतदाता इस लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी सूची में शामिल हैं। अदालत ने निर्देश दिया था कि दस्तावेज और आपत्तियां जमा करने के लिए पंचायत भवनों या प्रखंड कार्यालयों में कार्यालय स्थापित किए जाएं और राज्य सरकार चुनाव अधिकारियों को पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध कराए।

एसआईआर के नाम पर बंगाल से हटाए जा रहे 58 लाख वोट : सीएम ममता

ममता बनर्जी का आरोप है कि एसआईआर प्रक्रिया के नाम पर बंगाल में करीब 58 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं. जिनमें कई जीवित लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है. बता दें, करीब 15 सालों से ममता बनर्जी ने बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत रखी है और बीजेपी को यहां अपना दबदबा कायम करने नहीं दिया है. ममता समर्थकों का मानना है कि चुनाव में ममता को ना हरा सकने के बाद, उनके वोट कम कराकर चुनाव में धांधली की कोशिश की जा रही है।

लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण पर लगातार दूसरे दिन हंगामा

एजेंसी। नई दिल्ली

लोकसभा में राहुल गांधी की स्पीच पर लगातार दूसरे दिन हंगामा हुआ। राहुल ने मंगलवार दोपहर 2 बजे पूर्व आर्मी चीफ की अनपब्लिश्ड बुक के आर्टिकल को सदन में पेश किया। कहा- मुझे बोलने दिया जाए। उनके यह कहते ही एनडीए के सांसदों ने टोकना शुरू कर दिया। आज वे 14 मिनट तक बोलने की कोशिश करते रहे। इस बीच हंगामा तेज होता गया। राहुल ने सोमवार को भी 46 मिनट तक अपनी बात कहने की कोशिश की थी। आज हंगामा बढ़ने पर स्पीकर कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी ने राहुल को रोका और दूसरी पार्टियों के सांसदों को बोलने को कहा, लेकिन राहुल के समर्थन में सपा सांसद नरेश उत्तम पटेल, ळटउ सांसद शताब्दी रॉय और उ्टङ सांसद डी एम कातिर आनंद ने बोलने से इनकार कर दिया। विपक्षी सांसद नारेबाजी करते वेल में पहुंच गए। स्पीकर पीठासीन कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी की चेयर की तरफ विपक्षी सांसदों ने पेपर उछाले। इसके बाद कार्यवाही स्थगित कर दी गई। इसके बाद पीठासीन दिलीप सैकिया ने 8 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया।राहुल गांधी ने मंगलवार शाम को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लेटर लिखा। कहा, 'आज मुझे लोकसभा में बोलने से रोका जाना न केवल इस परंपरा का उल्लंघन है, बल्कि यह गंभीर चिंता भी पैदा करता है कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में मुझे राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोलने से जानबूझकर रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह दोहराना आवश्यक है कि राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्रपति के अभिभाषण का एक प्रमुख हिस्सा थी, जिस पर संसद में चर्चा किया जाना आवश्यक है।'कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत अन्य विपक्षी सांसदों ने लोकसभा से 8 सांसदों को निलंबित करने, अमेरिका-भारत ट्रेड डील, एपस्टीन समेत अन्य मुद्दों पर सदन के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने हाउडी मोदी-सरेंडर मोदी, नरेंद्र मोदी-सरेंडर मोदी, मोदी ट्रम्प-भाई भाई, देश बेचकर खाई मलाई और किसान विरोधी-नरेंद्र मोदी के नारे लगाए।लोकसभा से कांग्रेस के आठ सांसदों के निलंबन पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, 'यह बिल्कुल हास्यास्पद है।

चौसा कस्तूरबा कांड : प्रशासन सख्त, छह पर कार्रवाई, कई सवाल अब भी जिंदा

- मूक-बधिर छात्रा की मौत ने उजागर की आवासीय विद्यालयों की हकीकत, प्रशासन की सख्ती के बीच जवाबदेही की परीक्षा

केटी न्यूज/चौसा

चौसा प्रखंड के बनारपुर स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में 13 वर्षीय मूक-बधिर छात्रा की मौत ने जिले की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को कठघरे में खड़ा कर दिया है। घटना के बाद उठे जनाक्रोश और जांच रिपोर्ट के सामने आते ही जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। लापरवाही के आरोप में छह कर्मियों पर गाज गिरी है, जबकि विद्यालय के शीर्ष स्तर पर जिम्मेदारी निभा रहे प्रधानाध्यापक सह संचालक को निलंबित किया गया है। कार्रवाई तेज है, लेकिन सवाल उससे भी बड़े हैं क्या यह त्रासदी टाली जा सकती थी। जिलाधिकारी के निर्देश पर हुई संयुक्त जांच में साफ हुआ कि छात्रा की तबीयत बिगड़ने के बाद विद्यालय में न तो नियमित स्वास्थ्य निगरानी की व्यवस्था थी, न आपात स्थिति से निपटने का कोई प्रभावी प्रोटोकॉल। जांच रिपोर्ट के आधार पर केयर टेकर किरण कुमारी, वार्डन लक्ष्मी कुमारी, रसोइया आशा देवी और हीरा देवी, तथा रात्रि प्रहरी मुन्ना सिंह को तत्काल प्रभाव से सेवा से मुक्त कर दिया गया है। वहीं, मध्य विद्यालय बनारपुर के प्रधानाध्यापक-सह-कस्तूरबा विद्यालय संचालक अतहर परवेज को निलंबित किया गया है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हृषिकेश कुमार सिंह के अनुसार, घटना के तुरंत बाद केयर टेकर के विरुद्ध मुफस्सिल थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी चंदन द्विवेदी की संयुक्त जांच ने विद्यालय की कार्यप्रणाली में गंभीर खामियां उजागर कींकृदवाओं की उपलब्धता, समय पर चिकित्सकीय संपर्क और जिम्मेदारियों के स्पष्ट निर्धारण में चूक सामने आई। इन्हीं निष्कर्षों पर जिलाधिकारी सहिला ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।

घटना ने प्रशासनिक जवाबदेही पर बहस तेज कर दी है। परिजनों का आरोप है कि यदि समय रहते बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलती, तो जान बचाई जा सकती थी। आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाली विशेष आवश्यकता वाली छात्राओं के लिए अतिरिक्त सावधानी और प्रशिक्षित देखरेख अनिवार्य होती है, लेकिन इस मामले में व्यवस्था कागजों तक सिमटी दिखी। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई संदेश हैकृबच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं होगा। अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे और कानूनी कदम भी उठाए जा सकते हैं। साथ ही, सभी आवासीय विद्यालयों में स्वास्थ्य प्रबंधन, आपातकालीन प्रतिक्रिया और निगरानी व्यवस्था की व्यापक समीक्षा के निर्देश दिए गए हैं। कस्तूरबा कांड केवल एक स्कूल की कहानी नहीं, बल्कि सिस्टम की कसौटी है। कार्रवाई हुई है, पर असली परीक्षा अब है, क्या यह सुधारों में बदलेगी, या फिर अगली चेतावनी तक सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा।

56 प्रतिशत अधिप्राप्ति, 90 प्रतिशत भुगतान के बीच जिलाधिकारी साहिला ने सिस्टम को कसने के दिए सख्त निर्देश

धान अधिप्राप्ति में बक्सर ने पकड़ी रफ्तार, लेकिन लक्ष्य अभी दूर

केटी न्यूज/बक्सर

जिले में धान अधिप्राप्ति की रफ्तार भले ही बीते वर्ष की तुलना में तेज हुई हो, लेकिन निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने की चुनौती अभी भी बरकरार है। इसी कड़ी में मंगलवार को जिलाधिकारी साहिला की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में धान अधिप्राप्ति जिला टास्क फोर्स की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अधिप्राप्ति की प्रगति, किसानों के भुगतान की स्थिति और चावल आपूर्ति (सीएमआर) जैसे अहम बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई।

अबतक लक्ष्य का सिर्फ 56 प्रतिशत ही हासिल

समीक्षा के दौरान सामने आए आंकड़ों के अनुसार जिले में अब तक 8503 किसानों से 78,025.75 मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की जा चुकी है। यह जिले को मिले कुल लक्ष्य का 56.17 प्रतिशत ही है। हालांकि राहत की बात यह रही कि किसानों के भुगतान की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है और अब तक 90.55 प्रतिशत किसानों को भुगतान किया जा चुका है। यह स्थिति जहां प्रशासन की कार्यप्रणाली में सुधार की ओर इशारा करती है, वहीं यह भी साफ करती है कि अधिप्राप्ति की गति को और तेज करने की जरूरत है, ताकि शेष किसानों को भी समय रहते लाभ मिल सके।

सीएमआर आपूर्ति में सुधार, रैंकिंग में उछाल

बैठक में यह भी बताया गया कि समितियों के माध्यम से अब तक 12,615 मीट्रिक टन कस्टम मिल्ड राइस (सीएमआर) की आपूर्ति राज्य खाद्य निगम को की जा चुकी है। यह उपलब्धि इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि पिछले अधिप्राप्ति वर्ष की तुलना में इस बार जिला बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। इसी बेहतर प्रदर्शन का नतीजा है कि राज्य स्तर पर बक्सर जिले की रैंकिंग सुधरकर 21वें स्थान पर पहुंच गई है। हालांकि प्रशासन का मानना है कि इस रैंकिंग से संतोष करने के बजाय जिले को शीर्ष पंक्ति में लाने का लक्ष्य तय करना होगा।

जिलाधिकारी का कड़ा रुख, रफ्तार और पारदर्शिता दोनों जरूरी

जिलाधिकारी साहिला ने बैठक के दौरान साफ शब्दों में कहा कि धान अधिप्राप्ति सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि यह सीधे किसानों के भरोसे और उनकी आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा विषय है। उन्होंने जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर को निर्देश दिया कि अधिप्राप्ति की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए और किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त न की जाए। वहीं जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम को सीएमआर के भुगतान में तेजी लाने और एफआरके (फोर्टिफाइड राइस कर्नेल) की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया, ताकि आपूर्ति श्रृंखला में कोई बाधा न आए।

निगरानी पर जोर, गड़बड़ी पर जीरो टॉलरेंस

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि धान अधिप्राप्ति की पूरी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए। इसके लिए क्षेत्र में लगातार भ्रमणशील रहकर प्रभावी पर्यवेक्षण और अनुश्रवण करने को कहा गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर अनियमितता या किसानों की शिकायत सामने आने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में मौजूद रहे अधिकारी, जिम्मेदारी तय

इस अहम बैठक में वरीय उप समाहर्ता (अधिप्राप्ति), जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के माध्यम से न सिर्फ प्रगति की समीक्षा हुई, बल्कि आगामी दिनों के लिए स्पष्ट कार्ययोजना और जिम्मेदारियां भी तय की गईं। कुल मिलाकर, बक्सर जिले ने धान अधिप्राप्ति में सुधार के संकेत जरूर दिए हैं, लेकिन लक्ष्य की आधी दूरी पार करना ही काफी नहीं है। अब प्रशासन के सामने असली परीक्षा बाकी लक्ष्य को समय पर पूरा करने और हर किसान तक बिना बाधा लाभ पहुंचाने की है।

एक नजर

जिला नियोजनालय की पहल, स्वरोजगार के लिए योग्य युवाओं को मिलेगा नि:शुल्क टूल किट

बक्सर। जिले के बेरोजगार एवं प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में श्रम संसाधन विभाग, जिला नियोजनालय बक्सर द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। जिला नियोजन पदाधिकारी बक्सर से प्राप्त जानकारी के अनुसार नियोजन सेवा के विस्तार के तहत योग्य अभ्यर्थियों को विभिन्न ट्रेडों में निःशुल्क टूल किट उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि वे स्वयं का रोजगार शुरू कर आत्मनिर्भर बन सकें। इस योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटिशियन, प्लम्बर, इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सहित अन्य व्यवसायिक एवं तकनीकी ट्रेड में प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को संबंधित ट्रेड का टूल किट दिया जाएगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षित युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना तथा बेरोजगारी की समस्या को कम करना है। योजना का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी का बिहार राज्य का निवासी होना अनिवार्य है। साथ ही अभ्यर्थी की वार्षिक पारिवारिक आय अधिकतम तीन लाख रुपये होनी चाहिए तथा जिला नियोजनालय में न्यूनतम छह माह पूर्व से निर्बंधित होना आवश्यक है। लाभुकों के चयन में निबंधन की वरीयता को प्राथमिकता दी जाएगी। अभ्यर्थी को केंद्र अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम तीन माह का संबंधित ट्रेड में प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। इसके साथ ही अभ्यर्थी की आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। चयन प्रक्रिया में दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग तथा महिला अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। यह भी स्पष्ट किया गया है कि एक अभ्यर्थी को नियोजन विभाग द्वारा संचालित स्टडी किट एवं टूल किट योजना में से केवल एक योजना का ही लाभ दिया जाएगा। जो अभ्यर्थी पूर्व में स्टडी किट या टूल किट प्राप्त कर चुके हैं, वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे। आवेदकों को विहित प्रपत्र में सभी आवश्यक कागजातों की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ जिला नियोजनालय, बक्सर में आवेदन जमा करना होगा। इस योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 25 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। प्राप्त आवेदनों की जांच एवं लाभुकों का चयन उप निदेशक, नियोजन पटना प्रमंडल, पटना की अध्यक्षता में गठित त्रिसदस्यीय समिति द्वारा किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक अभ्यर्थी मोबाइल नंबर 8210044587 पर संपर्क कर सकते हैं।

परीक्षा केन्द्र पर बेहोश हुई छात्रा, छूटी परीक्षा, थानाध्यक्ष की तत्परता से बची जान

डुमरांव। इंटरमीडिएट परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों पर पड़ने वाला मानसिक दबाव एक बार फिर सामने आया, जब राज हाई स्कूल स्थित परीक्षा केंद्र पर एक छात्रा अचानक बेहोश हो गई। घटना दूसरी पाली की परीक्षा से ठीक पहले की है। उषारानी महारानी महाविद्यालय की इंटरमीडिएट छात्रा रोजी खातून परीक्षा देने केंद्र पर पहुंची ही थी कि उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और वह अचेत होकर गिर पड़ी। देखते ही देखते परीक्षा केंद्र पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए केंद्राधीक्षक ने बिना समय गंवाए डुमरांव थाने की पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा के नेतृत्व में पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने मानवीय संवेदनशीलता का परिचय देते हुए छात्रा को अपने वाहन से अनुमंडल अस्पताल डुमरांव पहुंचाया। समय पर अस्पताल पहुंचने से डॉक्टरों ने त्वरित प्राथमिक उपचार कर छात्रा की हालत को स्थिर कर लिया। अनुमंडल अस्पताल के चिकित्सकों के अनुसार छात्रा फिलहाल खतरे से बाहर है। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई गई है कि परीक्षा को लेकर अत्यधिक घबराहट और मानसिक तनाव के कारण यह स्थिति बनी। डॉक्टरों की टीम छात्रा की निगरानी कर रही है और आवश्यक उपचार जारी है। हालांकि इस अप्रत्याशित घटना के कारण छात्रा उस दिन की परीक्षा में शामिल नहीं हो सकी, लेकिन शिक्षा विभाग के नियमों के अनुसार वह संबंधित विषय की परीक्षा सप्लीमेंट्री के माध्यम से दे सकेगी। इससे उसका शैक्षणिक वर्ष प्रभावित नहीं होगा, जो छात्रा और उसके परिजनों के लिए बड़ी राहत है। घटना के बाद स्थानीय लोगों और परिजनों ने पुलिस की त्वरित कार्रवाई और संवेदनशील पहल की सराहना की। लोगों का कहना है कि यदि समय पर पुलिस और प्रशासन की मदद नहीं मिलती, तो स्थिति गंभीर हो सकती थी। यह घटना परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता को भी रेखांकित करती है।

बजट 2026 : स्वास्थ्य-शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और रोजगार पर है विशेष जोर : डॉ प्रियरंजन

केटी न्यूज/बक्सर

सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया वर्ष 2026 का बजट अब तक का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी बजट माना जा रहा है। इस बजट में राज्य के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। बजट का मूल उद्देश्य बिहार को ह्लसात निश्चय-3ह्व कार्यक्रम के माध्यम से विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करना है।

जिला प्रवक्ता भाजपा एवं महर्षि विश्वामित्र महाविद्यालय, बक्सर के स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉ. प्रिय रंजन चौबे ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह बजट संपूर्ण, समावेशी और विकासोन्मुखी है। उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य फोकस गरीबी उन्मूलन और समावेशी विकास पर है। इसके तहत प्रदेश के लगभग 94 लाख गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की ठोस योजना तैयार की गई है, जिससे समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को भी मुख्यधारा से जोड़ा जा सकेगा।

बजट में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, नए चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर इलाज की सुविधा और शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने, कौशल विकास को बढ़ावा देने और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के प्रावधान भी किए गए हैं।

महिला सशक्तिकरण को लेकर बजट में कई महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल की गई हैं, जिससे महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ेगी और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगी। किसानों, उद्यमियों, युवाओं और महिलाओं सहित समाज के सभी वर्गों का इस बजट में विशेष ध्यान रखा गया है।

कुल मिलाकर, बिहार का यह बजट राज्य के विकास को नई दिशा देने वाला, सामाजिक-आर्थिक संतुलन स्थापित करने वाला और भविष्य की मजबूत नींव रखने वाला बजट साबित होगा।

मुंगांव में जनता दरबार से स्कूल निरीक्षण तक पुलिस की सक्रियता से सुलझे विवाद, बढ़ा भरोसा

केटी न्यूज/डुमरांव

कोरानसराय थाना क्षेत्र के मुंगांव गांव में मंगलवार को आयोजित जनता दरबार ने पुलिस और ग्रामीणों के बीच भरोसे की एक मजबूत कड़ी को और सुदृढ़ कर दिया। थानाध्यक्ष माधुरी कुमारी की अध्यक्षता में हुए इस दरबार में ग्रामीणों की समस्याओं को सीधे सुना गया और त्वरित कार्रवाई के जरिए समाधान की दिशा तय की गई। जनता दरबार का उद्देश्य केवल शिकायतें सुनना नहीं, बल्कि मौके पर ही व्यावहारिक समाधान सुनिश्चित करना रहा। दरबार में कुल तीन मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया। इनमें दो विवाद रास्ते से जुड़े थे, जबकि एक मामला आपसी झगड़े और विधिक प्रक्रिया से संबंधित था। सभी मामलों को गंभीरता से सुनते हुए थानाध्यक्ष ने स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए। रास्ते और जमीन से जुड़े दो अन्य मामलों में भूमि मापी की आवश्यकता सामने आई, जिस पर अंचलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर विधिवत मापी कराने का आश्वासन दिया गया। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मापी पूरी होने तक विवादित स्थल पर किसी भी पक्ष की गतिविधि पर रोक के निर्देश भी दिए गए। इसी दौरान गांव के एक युवक द्वारा लोगों से पैसे लेकर वापस नहीं करने की शिकायत सामने आई। मामले को गंभीरता से लेते हुए थानाध्यक्ष ने संबंधित पक्ष को तलब कर आवश्यक कार्रवाई की और पीड़ितों को न्याय का भरोसा दिलाया। इस त्वरित हस्तक्षेप से ग्रामीणों में पुलिस के प्रति विश्वास और मजबूत हुआ।

जनता दरबार के बाद थानाध्यक्ष माधुरी कुमारी ने गांव के कई सरकारी विद्यालयों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विधि-व्यवस्था, सुरक्षा इंतजाम, बच्चों की उपस्थिति और परिसर की निगरानी व्यवस्था पर शिक्षकों से विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने बाहरी गतिविधियों पर नियंत्रण और बच्चों की सुरक्षित आवाजाही को लेकर आवश्यक सुझाव दिए। छोटे छात्र-छात्राओं से संवाद कर उन्होंने पढ़ाई, स्कूल सुविधाओं और सुरक्षा से जुड़ी बातों को जाना तथा निर्भीक होकर शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया।

डीएम साहिला ने बक्सर नगर परिषद क्षेत्र की योजनाओं का किया निरीक्षण, गुणवत्तापूर्ण कार्य और अतिक्रमण हटाने के निर्देश

- अटल कला भवन, स्टेडियम, सड़क चौड़ीकरण और गोलंबर सौंदर्यीकरण को लेकर दिए गए सख्त निर्देश

केटी न्यूज/बक्सर

जिलाधिकारी साहिला द्वारा नगर परिषद बक्सर अंतर्गत विभिन्न विकास योजनाओं एवं प्रगति यात्रा में घोषित कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी अविनाश कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी बक्सर, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण विभाग, कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद बक्सर सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं अभियंता उपस्थित रहे। निरीक्षण के क्रम में आईटीआई मैदान में निमार्णाधीन 620 सीट क्षमता वाले अटल कला भवन का जायजा लिया गया। कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण विभाग ने बताया कि कला, संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार, पटना द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसे दिसंबर 2026 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। जिलाधिकारी ने निर्माण स्थल के आसपास साफ-सफाई सुनिश्चित कराने एवं योजना से संबंधित डिस्प्ले बोर्ड लगाने का निर्देश दिया।

आईटीआई मैदान में प्रस्तावित स्टेडियम निर्माण को लेकर जानकारी देते हुए भवन निर्माण निगम के अभियंता ने बताया कि निविदा प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। कनीय अभियंता ने बताया कि स्टेडियम का प्रस्तावित नक्शा विभाग स्तर पर संशोधित किया गया है, जिसे प्राप्त होते ही एक सप्ताह के भीतर निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा।

पथ चौड़ीकरण कार्य की समीक्षा के दौरान कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल ने बताया कि कुल 4.20 किलोमीटर लंबाई में सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। नाला पर चेकर टाइल्स, पेवर ब्लॉक, फुटपाथ निर्माण एवं बिटुमिनस कार्य शेष है। जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिया कि सड़क निर्माण गुणवत्तापूर्ण हो तथा सड़क के लेवल के अनुरूप नालों का निर्माण कराया जाए, ताकि वर्षा जल की निकासी सुचारू रूप से हो और जलजमाव की समस्या उत्पन्न न हो।

निरीक्षण के दौरान नगर परिषद को निर्देश दिया गया कि आईटीआई मैदान के आसपास अवैध एवं अस्थायी अतिक्रमण को नियमानुसार एक सप्ताह के भीतर हटाया जाए। साथ ही सड़कों, पेड़ों और होर्डिंग पर जमी धूल की नियमित सफाई एवं मैदान के आसपास स्वच्छता सुनिश्चित करने को कहा गया। गोलंबर के पास खाली भूमि पर वेडिंग जोन निर्माण एवं चिन्हित स्थलों पर नो पार्किंग बैनर लगाने का भी निर्देश दिया गया।

जिलाधिकारी ने बक्सर गोलंबर के आसपास अवैध अतिक्रमण के कारण लगने वाले जाम पर नाराजगी जताते हुए क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराने एवं गोलंबर पार्क को और अधिक आकर्षक बनाने हेतु समन्वय के साथ कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया। वहीं, वरुणा बक्सर रेलवे फ्लाईओवर को लेकर बताया गया कि बस स्टैंड के समीप प्रस्तावित गोलंबर निर्माण से भविष्य में बढ़ने वाले यातायात को नियंत्रित करने में सुविधा होगी।

Mob: 9122226720
कुमार आर्थोपेडिक्स क्लिनिक
सुमित्रा महिला कॉलेज से पूरब, बेलवानी मोड़, डुमरॉव
डा. बिरेन्द्र कुमार
आर्थोपेडिक सर्जन
हड्डी, नस, गठिया रोग विशेषज्ञ
डा. एस.के. अम्बष्ठ
M.B.B.S (MKCC, ODISHA)
MD (Derma & Cosmetology),
KMC Manipal (Gold Medalist)
चर्म रोग, कुष्ट रोग, गुप्त रोग, सौंदर्य विशेषज्ञ
प्रत्येक मंगलवार
डा. अरूण कुमार
जेनरल एण्ड लेप्रोस्कोपिक सर्जन
(M.B.B.S, D.NB. (New Delhi)
पेट रोग विशेषज्ञ
प्रत्येक गुरूवार

इंटर परीक्षा में कदाचार पर जीरो टॉलरेंस, डुमरांव प्रशासन ने कसा शिकंजा

- परीक्षा केंद्रों के आसपास सख्ती, समय से पहुंचने और नियमों के पालन की सख्त हिदायत

केटी न्यूज/डुमरांव

डुमरांव में इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर प्रशासन ने इस बार सख्ती की नई मिसाल पेश की है। कदाचारमुक्त, शांतिपूर्ण और पारदर्शी परीक्षा आयोजन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अनुमंडल प्रशासन और पुलिस विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। परीक्षा अवधि के दौरान नगर क्षेत्र सहित आसपास के सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या अनुचित गतिविधि पर तुरंत नियंत्रण किया जा सके।

एसडीपीओ पोलस्त कुमार के नेतृत्व में डुमरांव थाना पुलिस द्वारा व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। थानाध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा ने बताया कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र के बाहर और आसपास पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसके साथ ही संवेदनशील परीक्षा केंद्रों को चिन्हित कर वहां अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है। परीक्षा के दौरान लगातार पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है, जिससे असामाजिक तत्वों और अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा सके।

प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षा केंद्रों के आसपास अनावश्यक भीड़, ठेला-खोमचा लगाने, अभिभावकों के जमावड़े या किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। पुलिस द्वारा परीक्षा केंद्रों के आसपास विशेष निगरानी रखी जा रही है, ताकि परीक्षार्थियों को शांत और सुरक्षित माहौल मिल सके।

थानाध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा ने परीक्षार्थियों को समय पालन को लेकर भी सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि सभी छात्र-छात्राओं को निर्धारित समय से पहले अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य है। देरी से पहुंचने की स्थिति में परीक्षा में शामिल होने में परेशानी हो सकती है, जिसकी जिम्मेदारी परीक्षार्थियों की स्वयं की होगी।

इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों में मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री ले जाने पर पूर्ण रोक लगाई गई है। परीक्षा से संबंधित दिशा-निर्देशों का पालन न करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन ने अभिभावकों और आम नागरिकों से भी सहयोग की अपील की है। किसी भी आपात स्थिति या समस्या की जानकारी तुरंत नजदीकी पुलिस कर्मी या प्रशासनिक अधिकारियों को देने को कहा गया है। प्रशासन का मानना है कि कड़ी निगरानी और जनसहयोग से ही निष्पक्ष और कदाचारमुक्त परीक्षा का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।

मंदिर पथ, बाईपास, फ्लाईओवर से लेकर बिजली-पानी तक की योजनाओं की गहन समीक्षा

प्रगति योजनाओं पर डीएम साहिला सख्त

लापरवाह अफसरों पर कार्रवाई के संकेत

- तय समय-सीमा में काम पूरा करने का अल्टीमेटम

केटी न्यूज/बक्सर

जिले में चल रही तकनीकी विभागों की योजनाओं को लेकर प्रशासन अब किसी भी तरह की ढिलाई के मूड में नहीं है। जिलाधिकारी साहिला की अध्यक्षता में समाहरणालय परिसर स्थित सभाकक्ष में मंगलवार को तकनीकी विभाग, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप एवं प्रगति यात्रा से संबंधित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सड़क, बिजली, पुल, जलापूर्ति, सिंचाई और कृषि से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की बारीकी से पड़ताल की गई और कई विभागों को सख्त निर्देश जारी किए गए।

बैठक में बाबा ब्रह्ममेश्वर नाथ मंदिर पथ के चौड़ीकरण कार्य में हो रही देरी पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। उन्होंने पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया कि चौड़ीकरण का कार्य शीघ्र पूरा कराया जाए। साथ ही सड़क के मार्ग में पड़ने वाले विद्युत खंभों को उचित स्थान पर स्थानांतरित कराने के लिए विद्युत प्रमंडल बक्सर को भी तत्काल कार्रवाई का आदेश दिया गया।

धनसोई बाईपास पथ के निर्माण में भू-अर्जन की प्रक्रिया को लेकर भी जिलाधिकारी ने सख्त रुख अपनाया। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि संबंधित कार्रवाई यथाशीघ्र पूरी की जाए, ताकि निर्माण कार्य में कोई बाधा न आए। इसी क्रम में इंजीनियरिंग कॉलेज महदह के पहुंच पथ के निर्माण कार्य को भी अविलंब पूर्ण करने का आदेश दिया गया।

ग्रामीण कार्य विभाग डुमरांव के कार्यपालक अभियंता द्वारा बैठक में पूर्ण प्रगति प्रतिवेदन एवं फोटोग्राफ्स उपलब्ध नहीं कराए जाने पर डीएम ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। पूर्व में स्मारित किए जाने के बावजूद रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने और कार्यों में शिथिलता बरतने के कारण उनसे कारण पृच्छा करने का निर्देश दिया गया।

जनता दरबार में अत्यधिक विद्युत बिल से संबंधित बढ़ती शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कार्यपालक अभियंता विद्युत आपूर्ति प्रमंडल बक्सर को निर्देश दिया गया कि विशेष कैम्प लगाकर ऐसे मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करें। इसके साथ ही नगर परिषद क्षेत्र में सर्विस विद्युत तारों और नीचे लटके हुए तारों को भूमिगत करने के लिए कार्य योजना तैयार करने का भी आदेश दिया गया।

बैठक में एनएचएआई के किसी भी प्रतिनिधि की अनुपस्थिति पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और कार्यपालक अभियंता एनएचएआई से कारण पृच्छा करने का निर्देश दिया। वहीं प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि नहीं होने पर व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए।

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्यों के लिए विद्युत कनेक्शन देने को लेकर डीएम ने कृषि विभाग से बेहतर समन्वय पर जोर दिया। किसान सलाहकार, कृषि समन्वयक और प्रखंड कृषि पदाधिकारी के साथ तालमेल स्थापित कर पंचायत स्तर पर कैम्प लगाने के निर्देश दिए गए।

आरओबी बक्सर वरूणा रेलवे फ्लाईओवर को 15 मार्च तक हर हाल में पूरा करने का निर्देश पुल निर्माण निगम को दिया गया। साथ ही निमार्णाधीन गहमर-चौसा फ्लाईओवर के किनारे वाले मार्ग पर पर्याप्त मात्रा में मिट्टी गिराने का आदेश दिया गया, ताकि आम जनता को आवागमन में परेशानी न हो।

भभुअर तालाब के जीर्णोद्धार कार्य को मार्च तक पूरा करने का निर्देश लघु सिंचाई प्रमंडल बक्सर को दिया गया। वहीं केशोपुर बहुग्रामीय जलापूर्ति योजना के तहत प्रत्येक 10 दिन पर सभी वार्डों में आपूर्ति किए जा रहे पानी के सैंपल की जांच कर रिपोर्ट समर्पित करने का आदेश लोक स्वास्थ्य प्रमंडल को दिया गया।

बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल अंतर्गत कोईलवर तटबंध पर बन रही सड़क के लिए प्रभावित रैयतधारियों की पहचान कर उचित मुआवजा भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश जिला भू-अर्जन पदाधिकारी और बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल को दिया गया।

बैठक के अंत में जिलाधिकारी साहिला ने दो टूक कहा कि सभी योजनाएं समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरी हों। लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

एक नजर

राजपुर में दिव्यांग बच्चों के लिए प्रमाणीकरण शिविर आयोजित

राजपुर। समावेशी शिक्षा को धरातल पर उतारने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों को सशक्त बनाने की दिशा में राजपुर प्रखंड में एक अहम पहल की गई। बीआरसी परिसर में बिहार शिक्षा परियोजना के तत्वावधान में दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष प्रमाणीकरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग के पूर्व से नामांकित दिव्यांग छात्र-छात्राओं की जांच की गई। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग बच्चों की पहचान, प्रमाणीकरण और उनकी जरूरतों के अनुसार सहायक उपकरण उपलब्ध कराना रहा, ताकि वे शिक्षा की मुख्यधारा से जुड़ सकें। शिविर में पहुंचे बच्चों की शारीरिक एवं शैक्षणिक स्थिति का आकलन विशेषज्ञों और शिक्षकों की टीम द्वारा किया गया। प्रमाणीकरण के बाद आगामी दिनों में इन बच्चों को व्हीलचेयर, ट्राई साइकिल, एमआर किट, लो विजन किट, ब्रेल किट, वाइट केन और बैसाखी जैसे सहायक उपकरण प्रदान किए जाएंगे।

शिविर में विभिन्न गांवों से आए मूकबधिर, अस्थि दिव्यांग, दृष्टिबाधित सहित अन्य श्रेणी के लगभग 40 दिव्यांग बच्चों ने भाग लिया। बच्चों के साथ अभिभावक भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस पहल को सराहते हुए कहा कि ऐसे शिविरों से उनके बच्चों को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा।

मौके पर मौजूद शिक्षकों ने बताया कि समावेशी शिक्षा का लक्ष्य सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं है, बल्कि दिव्यांग बच्चों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने में मदद करना भी है। इस अवसर पर दिलीप मिश्रा, आनंद मिश्रा, आशुतोष शर्मा, राहुल गुप्ता, दिनेश प्रसाद सिंह सहित अन्य शिक्षा कर्मी और सहयोगी उपस्थित रहे। कार्यक्रम दोपहर तक चला और इसे सफल बनाने में सभी कर्मियों की सक्रिय भूमिका रही।

राजपुर में भीषण सड़क हादसा, दो बाइक की टक्कर में युवक की मौत, तीन गंभीर घायल

राजपुर। राजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चौसाझकोचस मुख्य मार्ग पर मकोरियाडीह गांव के समीप सोमवार को तेज रफ्तार दो बाइकों की आमने-सामने हुई टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इतना जबरदस्त था कि दोनों बाइक के परखच्चे उड़ गए और सड़क पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। मृतक की पहचान धनसोई थाना क्षेत्र के मानिकपुर गांव निवासी 30 वर्षीय प्रवीण पांडेय, पिता चंद्रभूषण पांडेय के रूप में की गई है। घायलों में मानिकपुर गांव निवासी 26 वर्षीय नीरज पांडेय पिता स्व. झरोरा पांडेय, 45 वर्षीय विनीत उर्फ छोटू पांडेय पिता हृदयशंकर पांडेय तथा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कृतपुरा गांव निवासी 24 वर्षीय गोलू कुमार पिता भोला साह शामिल हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार प्रवीण पांडेय अपने दोस्तों के साथ एक ही बाइक पर सवार होकर बक्सर की ओर जा रहे थे। मकोरियाडीह के पास बगल से गुजर रही एक पिकअप वाहन से बचने के प्रयास में उन्होंने ओवरटेक किया, इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही दूसरी बाइक से उनकी टक्कर हो गई। टक्कर के बाद दोनों बाइक सवार सड़क पर गिर पड़े। घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। इसी दौरान उत्तर प्रदेश के भावरकोल थाना क्षेत्र के खड़िया गांव निवासी आसू राय ने मानवता का परिचय देते हुए एक ऑटो रोककर सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजपुर पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल बक्सर रेफर कर दिया गया, जहां प्रवीण पांडेय की अस्पताल पहुंचते ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही राजपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों दुर्घटनाग्रस्त बाइकों को कब्जे में लेकर थाने ले गई। थाना अध्यक्ष निवास कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। घटना की खबर मिलते ही मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया।

पटना प्रमंडल स्तरीय दिव्यांग खेल प्रतियोगिता 6 फरवरी को, बक्सर के खिलाड़ी लेंगे भाग

बक्सर। वार्षिक खेल कार्यक्रम 2025-26 के तहत खेल विभाग, बिहार एवं बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना के संयुक्त तत्वावधान में जिला प्रशासन, पटना द्वारा पटना प्रमंडल स्तरीय (अंतर-जिला) दिव्यांग खेल प्रतियोगिता 2025-26 का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य दिव्यांग खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का मंच उपलब्ध कराना तथा खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना है। यह प्रमंडल स्तरीय प्रतियोगिता 06 फरवरी (शुक्रवार) को पाटलिपुत्र खेल परिसर, कंकड़बाग, पटना में आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता में पटना प्रमंडल के विभिन्न जिलों से चयनित दिव्यांग खिलाड़ी भाग लेंगे। आयोजन को लेकर खेल विभाग द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रतियोगिता के अंतर्गत एथलेटिक्स, दृष्टिबाधित क्रिकेट एवं दृष्टिबाधित फुटबॉल जैसी खेल विधाओं का आयोजन किया जाएगा। एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए आयु सीमा निर्धारित की गई है। वार्षिक खेल कार्यक्रम 2025-26 में निर्धारित अर्हता एवं मापदण्डों के अनुसार एथलेटिक्स स्पर्धा में वही खिलाड़ी भाग ले सकेंगे, जिनकी आयु एक दिसंबर 2025 को 30 वर्ष तक होगी। वहीं दृष्टिबाधित क्रिकेट एवं दृष्टिबाधित फुटबॉल प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। बक्सर जिले से प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक दिव्यांग खिलाड़ी पांच फरवरी तक उपाधीक्षक, शारीरिक शिक्षा कार्यालय, एम.पी. उच्च विद्यालय, बक्सर में अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के समय खिलाड़ियों को आवश्यक प्रमाण-पत्र एवं दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

कसम धरती माई ने खोली नशे की साजिश की परतें, महादलित बस्ती में जागी चेतना

केटी न्यूज/राजपुर

प्रखंड के बन्नी पंचायत अंतर्गत भरखरा गांव की महादलित बस्ती उस समय सामाजिक चेतना का केंद्र बन गई, जब वहां भोजपुरी नाटक ह्लकसम धरती माईह्व का सशक्त मंचन किया गया। गांव की चौपाल पर सजी यह रंगमंचीय प्रस्तुति केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने समाज में तेजी से पनप रही नशा प्रवृत्ति और उसके पीछे छिपी साजिशों को बेनकाब कर दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ बीडीसी प्रतिनिधि अखिलेश कुमार एवं समाजसेवियों द्वारा संत शिरोमणि रविदास के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया। इसके बाद कलाकारों का परिचय हुआ और नाटक की शुरूआत होते ही दर्शक भावनात्मक रूप से कथा से जुड़ते चले गए। नाटक का निर्देशन कपिल राम ने किया, जिन्होंने कथा को जमीन से जोड़ते हुए बेहद प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। नाटक की कहानी गांव-समाज के उस कड़वे सच को सामने लाती है, जहां शिक्षा के अभाव में युवा पीढ़ी भटकाव का शिकार होकर कम उम्र में ही नशे की गिरफ्त में आ जाती है। मंच पर यह दृश्य जीवंत रूप में उभरा कि किस तरह नशे की लत युवाओं को उनके परिवार, समाज और जिम्मेदारियों से दूर कर देती है। कलाकारों ने यह भी दर्शाया कि नशे के बड़े सौदागर किस प्रकार समाज को धीरे-धीरे कमजोर करते हैं और जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाता है, उसे दबाने की हरसंभव कोशिश करते हैं। नाटक के संवाद, गीत और अभिनय ने दर्शकों को झकझोर दिया।

कई दृश्य ऐसे रहे, जिनमें सन्नाटा छा गया और आंखें नम हो गईं। ग्रामीणों ने कहा कि आधुनिकता की दौड़ में जहां गांव की संस्कृति और लोक कला पीछे छूटती जा रही है, वहीं इस तरह के नाटक समाज को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। इस प्रस्तुति में कलाकार गौतम कुमार, सुभाष राम, अर्जुन कुमार, चंदन कुमार, अंतू राम और गोरख कुमार ने अपने सशक्त अभिनय से जान डाल दी। दर्शकों ने कलाकारों की जमकर सराहना की और कहा कि यह नाटक स्थानीय युवाओं को नशे से दूर रहने और शिक्षा की ओर बढ़ने की प्रेरणा देगा। कुल मिलाकर, कसम धरती माई नाटक ने मनोरंजन के साथ-साथ सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश देकर गांव में जागरूकता की मजबूत लकीर खींची।

रामकथा की गूंज से गूंज उठा कमरपुर

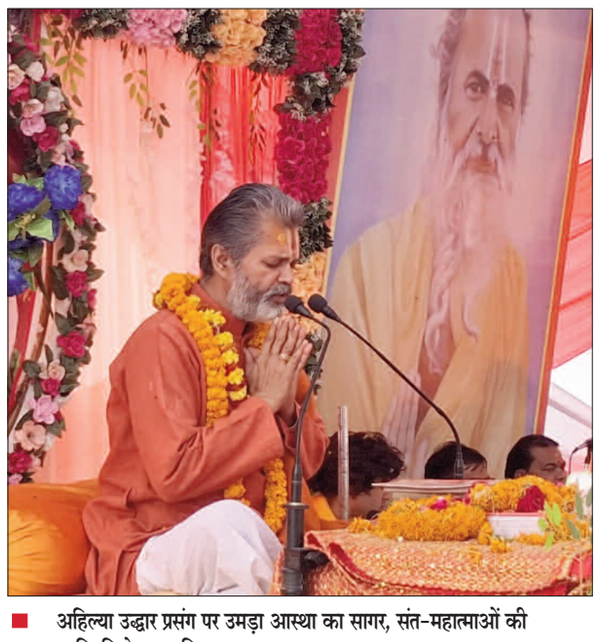

- अहिल्या उद्धार प्रसंग पर उमड़ा आस्था का सागर, संत-महात्माओं की उपस्थिति ने रचा इतिहास

केटी न्यूज/बक्सर

कमरपुर स्थित श्री हनुमत धाम मंदिर इन दिनों भक्ति, श्रद्धा और सनातन संस्कृति के अद्भुत संगम का साक्षी बन रहा है। श्री सद्गुरुदेव पुण्य स्मृति महोत्सव के चौथे दिन जैसे ही रामकथा का प्रवाह शुरू हुआ, पूरा क्षेत्र आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर हो गया। हजारों श्रद्धालु, साधु-संत और ग्रामीण भक्त एक साथ प्रभु श्रीराम की कथा में डूबते चले गए।

राम के चरण स्पर्श से चेतना में लौटी अहिल्या

चौथे दिन की कथा में अयोध्या से पधारे प्रख्यात कथा व्यास पंडित विजय नारायण शरण जी ने अहिल्या उद्धार प्रसंग का भावपूर्ण वर्णन किया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या श्रापवश शिला बन गई थीं, लेकिन प्रभु श्रीराम के चरणों की रज मात्र से उनका उद्धार हो गया।

व्यास जी ने कहा कि श्रीराम केवल मयार्दा पुरुषोत्तम ही नहीं, बल्कि करुणा और कृपा के जीवंत स्वरूप हैं। उनका स्पर्श केवल शरीर को नहीं, बल्कि आत्मा को भी जागृत करता है। कथा के इस प्रसंग पर श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गईं और पूरा पंडाल जय श्रीराम के उद्घोष से गूंज उठा।

जनकपुर नगर दर्शन ने बांधा समां

कथा के अगले क्रम में प्रभु श्रीराम और लक्ष्मण के जनकपुर नगर भ्रमण का वर्णन किया गया। जैसे ही व्यास जी ने जनकपुर की अलौकिक छटा और वहां के लोगों की भावनाओं को शब्दों में उकेरा, श्रोता उस दृश्य को मन ही मन देखने लगे। भजन-कीर्तन के दौरान श्रद्धालु झूम उठे और वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया।

साधु-संतों की उपस्थिति ने दिया महाकुंभ सा स्वरूप

चौथे दिन के आयोजन की सबसे बड़ी विशेषता रही हजारों साधु-संतों की गरिमामयी मौजूदगी। बक्सर सहित आसपास के जिलों से पहुंचे संत-महात्माओं ने पूज्य मामा जी महाराज एवं श्री महात्मा जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। संतों के सान्निध्य ने पूरे आयोजन को एक आध्यात्मिक महाकुंभ का स्वरूप दे दिया।

आज होगा महोत्सव का समापन, विशाल भंडारे का आयोजन

आयोजन समिति के अनुसार, 4 फरवरी (बुधवार) को महोत्सव का अंतिम दिन होगा। दोपहर 1 बजे से विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। समिति ने सभी श्रद्धालुओं से इस पावन अवसर पर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करने और धर्मलाभ लेने की अपील की है।

कमरपुर इन दिनों केवल एक गांव नहीं, बल्कि आस्था और भक्ति का जीवंत तीर्थ बन चुका है।

जिला नियोजनालय बक्सर में स्टडी किट योजना के लिए आवेदन आमंत्रित, प्रतियोगी परीक्षार्थियों को मिलेगा निःशुल्क लाभ

केटी न्यूज/बक्सर

जिला नियोजन पदाधिकारी बक्सर से प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग द्वारा संचालित स्टडी किट योजना के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। यह योजना पूर्णतः निःशुल्क है, जिसका उद्देश्य जिले के आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहायता प्रदान करना है।

इस योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना सहित अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को स्टडी किट उपलब्ध कराई जाएगी। स्टडी किट में प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित आवश्यक पुस्तकें, नोट्स, डायरी, मानचित्र, कलम सहित अन्य अध्ययन सामग्री शामिल होगी, जिससे अभ्यर्थियों को तैयारी में सुविधा मिल सके।

योजना का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थियों का जिला नियोजनालय में न्यूनतम छह माह का निबंधन होना अनिवार्य है। साथ ही सरकारी सेवा में रिक्त पदों के विरुद्ध आवेदन किए जाने का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। आवेदक की आयु सीमा सरकारी सेवा के मापदंडों के अनुसार 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आवेदक बिहार राज्य का निवासी हो तथा वार्षिक पारिवारिक आय तीन लाख रुपये से अधिक न हो। शैक्षणिक योग्यता परीक्षा के अनुसार मान्य होना आवश्यक है। लाभुकों के चयन में दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं महिला अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि, पूर्व में स्टडी किट अथवा टूल किट का लाभ प्राप्त कर चुके अभ्यर्थी इस योजना के पात्र नहीं होंगे। जिला नियोजन पदाधिकारी प्रणय प्रतीक ने जिले के सभी इच्छुक छात्र-छात्राओं से अपील की है कि वे सरकारी आईटीआई, चरित्रवन बक्सर स्थित जिला नियोजनालय में अपना आवेदन पत्र जमा करें। उन्होंने बताया कि आवेदन प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर सभी पात्र अभ्यर्थियों को स्टडी किट उपलब्ध करा दी जाएगी। यह योजना जिले के युवाओं के लिए सरकारी सेवा के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।

नीतीश सरकार के पेश बजट से बिहार में विकास की होगी नई उड़ान : अरुणा देवी

केटी न्यूज/रोहतास

सीएम के नेतृत्व में बिहार के वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने मंगलवार को 2026-27 का बजट सदन के पटल पर रख विकास को दिया नया रफ्तार। जो पेश संपन्न बिहार,समृद्ध बिहारह्ल की थीम पर आधारित इस बजट में विकास, रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके पेश बजट के प्रति आभार व्यक्त करते हुए जदयू राज्य परिषद सदस्य सह तरारी विधानसभा प्रभारी अरुणा देवी ने पेश बजट पर मुख्यमंत्री

नीतीश कुमार का आभार व्यक्त

करते हुए कहा कि इस बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उदेश्य से हाट-बाजार विकास को भी बजट में खास ध्यान रखा गया है। बिहार के बजट का कुल आकार 3.44 लाख करोड़ रुपये रखा गया है। साथ ही उद्योग और रोजगार को रफ्तार मिलेगी। सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 में औद्योगिक विकास पर विशेष फोकस किया है। उद्योग और रोजगार को गति देने के लिए सरकार ने बजट में उद्योग क्षेत्र के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे नए उद्योगों को प्रोत्साहन, निवेश आकर्षित करने के साथ साथ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित का लक्ष्य रखा गया है। बजट में स्टार्टअप और लघु उद्योगों को भी प्रोत्साहन देने की व्यवस्था किया गया है। इसके साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी बजट में विशेष रूप से प्रवधान किया गया है। इसके लिए सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए हाट-बाजार विकास योजना को पर जोर देगी। ताकि हाट-बाजार सुदृढ़ हो। इससे किसानों, छोटे व्यापारियों और स्थानीय उत्पादों को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही किसानों पर भी विशेष रूप से फोकस करते हुए कृषि रोड मैप के तहत किसानों को प्रोत्साहन देने पर जोर,कृषि उत्पादन,सिंचाई,भंडारण और विपणन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए नई योजनाएं भी लागू होगी। जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी भी होगी। जबकि सरकार का दावा है कि यह बजट राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत करने और हर वर्ग को विकास से जोड़ने की दिशा में अहम भूमिका अदा करेगा और आत्मनिर्भर और समृद्ध बिहार का निर्माण होगा।

जनगणना को लेकर नीतीश सरकार ने शुरू की तैयारी, समन्वय समिति की हुई बैठक

एजेंसी। पटना

साल 2027 में पूरे देश में होने वाली जनगणना को लेकर बिहार सरकार ने तैयारियां तेज कर दी है। इसको लेकर मंगलवार को राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति की दूसरी महत्वपूर्ण बैठक पुराना सचिवालय के सम्मेलन कक्ष में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने की। बैठक में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारियों ने भाग लेकर जनगणना से जुड़ी तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में स्पष्ट किया गया कि भारत सरकार द्वारा जारी सीमा स्थिरीकरण अधिसूचना के तहत 31 दिसंबर 2025 से 31 मार्च 2027 तक राज्य में किसी भी ग्रामीण या शहरी प्रशासनिक इकाई की सीमा अथवा क्षेत्राधिकार में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। वर्तमान में बिहार में 534 ग्रामीण एवं 265 शहरी प्रशासनिक इकाइयाँ (एक छावनी परिषद सहित) अधिसूचित हैं, जिनके आधार पर ही जनगणना कार्य संपन्न होगा। बैठक में बताया गया कि जनगणनाझ्2027 दो चरणों में आयोजित की जाएगी। पहला चरण मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना होगा, जिसे अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच 30 दिनों की अवधि में संपन्न किया जाएगा। इस चरण के निष्पादन की अवधि तय करने तथा उससे संबंधित अधिसूचना राज्य राजपत्र में प्रकाशित कराने की जिम्मेदारी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को नोडल विभाग के रूप में सौंपी गई है। इस चरण में कुल 33 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो मकानों की स्थिति, उपयोग, उपलब्ध सुविधाएँ, परिसंपत्तियाँ तथा मुख्य अनाज के उपभोग से संबंधित होंगे। इन प्रश्नों को भारत सरकार द्वारा 23 जनवरी 2026 को विधिवत अधिसूचित किया जा चुका है। बैठक में निर्देश दिया गया कि प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी शीघ्र ही जिला जनगणना पदाधिकारी, अन्य कनीय जनगणना पदाधिकारी, तथा जिला स्तरीय जनगणना समन्वय समिति का गठन सुनिश्चित करें। साथ ही, जिला एवं प्रभार स्तर पर जनगणना कोषांग की स्थापना और सुदृढ़ीकरण को प्राथमिकता दी जाए। विशेष रूप से जिलों को निर्देशित किया गया कि वे अपने क्षेत्र के विशेष क्षेत्रों जैसे छावनी, सैन्य एवं अर्धसैन्य क्षेत्र तथा प्रतिबंधित क्षेत्रों जैसे कारागार, रेलवे परिसर, वन क्षेत्र, तापीय विद्युत कॉलोनी आदि की प्रमाणित सूची तैयार कर जनगणना कार्य निदेशालय, बिहार को उपलब्ध कराएं।

पूर्णत: डिजिटल माध्यम से जनगणना

बैठक में यह भी बताया गया कि जनगणनाझ्2027 पहली बार पूर्णतः डिजिटल माध्यम से होगी। इसके लिए क्षेत्राधिकार परिवर्तन पोर्टल से क्षेत्राधिकार अद्यतन, जनगणना प्रबंधन एवं अनुश्रवण प्रणाली से नियुक्ति-पत्र, पहचान-पत्र और डिजिटल प्रभार पंजिका, मकान सूचीकरण खंड निर्माण पोर्टल से डिजिटल मानचित्र तैयार करना तथा नागरिकों के लिए स्वगणना की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

सेवा-हितों की सुरक्षा पर चर्चा

बैठक में जनगणना कार्य में लगे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सेवा-हितों की सुरक्षा के लिए जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 15(क) तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 27 के प्रावधानों पर भी प्रकाश डाला गया। बैठक के अंत में मुख्य सचिव ने सभी विभागों के बीच प्रभावी समन्वय को और सुदृढ़ करने पर बल देते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए, ताकि जनगणनाझ्2027 का कार्य पारदर्शी, सुचारु और समयबद्ध ढंग से संपन्न हो सके। बैठक में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ पदाधिकारी समिति के सदस्य के रूप में उपस्थित रहे। इनमें सी. के. अनिल, प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग-सह-राज्य समन्वयक (जनगणना); डॉ. बी. राजेंदर, अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग एवं शिक्षा विभाग; विनय कुमार, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग; मयंक वरवड़े, सचिव, योजना एवं विकास विभाग; वंदना प्रेयषी, सचिव, समाज कल्याण विभाग; जय सिंह, सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधारविभाग; मनोज कुमार, सचिव, पंचायती राज विभाग; रंजीत कुमार, निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय; विष्णु भूषण चौधरी, अपर सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा एम. रामचंद्रुडु, निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, बिहार सह-संयोजक सदस्य के रूप में शामिल थे। इसके अतिरिक्त जनगणना कार्य निदेशालय, बिहार के संयुक्त निदेशक, उप निदेशकगण, सहायक निदेशकगण एवं अन्य अधिकारीगण भी बैठक में उपस्थित रहे।

सीएम के पेश बजट से बिहार में स्वास्थ-शिक्षा के साथ रोजगार के बहुरेंगे दिन : डॉ. मनीष

केटी न्यूज/रोहतास

केंद्रीय बजट पेश के बाद अब बिहार के वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव द्वारा जारी वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को बिहार के नजरिए से लोगों ने इसे संतुलित और समावेशी बजट बताया है। जो पेश बजट लगभग 3.66 लाख करोड़ रुपये का अनुमानित है। जिसे पिछले सत्र के 3.17 लाख करोड़ की बजट से करीब 11 प्रतिशत अधिक आकलन है। इस पर खुशी जताते हुए एनडीए समर्थित भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सह काराकाट विधासभा नेता डॉ.मनीष रंजन ने बताया कि नए सत्र के पेश बजट से बिहार में डबल इंजन की सरकार में महिला सशक्तिकरण के साथ स्वास्थ-शिक्षा के साथ रोजगार क्षेत्र में भी लोगों को एक नई उड़ान मिलेगी। जिसके तहत बिहार में पात्र महिलाओं को रोजगार के लिए 2-2 लाख रुपये की सहायता देने की घोषणा की गई है। जिसके अंतर्गत पटना में 'पिंक बस' सेवा और 'महिला हाट' की शुरूआत जैसी नई

पहल को लोगों द्वारा काफी सराहा गया है। साथ ही शिक्षा क्षेत्र के लिए सर्वाधिक 60 हजार करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया है। किसान हित को ध्यान में रखते हुए कैंसर अस्पताल और राज्य में 108 नए शहरी चिकित्सा केंद्र खोलने का निर्णय जनता के बीच चर्चा में है। साथ ही डॉ. मनीष ने बताया कि राज्य की आर्थिक विकास दर 14.9 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है, जो राज्य के अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होने को दशार्ता है। दूसरी तरफ जहां सत्ता पक्ष और व्यापारिक संगठनों ने इसे 'विकसित बिहार' की दिशा में एक ठोस कदम बताया है, वहीं विपक्षी दलों ने इसे दिशाहीन करार देते हुए विशेष राज्य के दर्जे की मांग को अनसुना करने का आरोप लगाया है। बजट के नजरिए से ग्रामीण बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण पर जोर देने के कारण बिहार की जनता ने इसे सरकार सकारात्मक सोच बताया है। जिसका बिहार की जनता ने तहेदिल से इसका स्वागत किया है।

इंटरमीडिएट परीक्षा के दूसरे दिन भी दो परीक्षार्थी निष्काशित

कदाचारमुक्त परीक्षा को लेकर डीएम हुए सख्त

केटी न्यूज/नवादा

मंगलवार इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा के दूसरे दिन द्वितीय पाली में जिला पदाधिकारी,रवि प्रकाश द्वारा राजेन्द्र मेमोरियल वूमेंस कॉलेज,गांधी इंटर स्कूल, नवादा एवं बालिका इंटर स्कूल स्थित परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में जिला पदाधिकारी द्वारा परीक्षा केन्द्रों पर विधि-व्यवस्था, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था, परीक्षार्थियों के बैठने की समुचित व्यवस्था, सीसीटीवी निगरानी, प्रवेश-निकास व्यवस्था सहित कदाचार-मुक्त परीक्षा संचालन हेतु की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के निदेर्शों के आलोक में सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों एवं कर्मियों को स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं कदाचार-मुक्त परीक्षा संचालन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए।

निरीक्षण के दौरान आज द्वितीय पाली में गांधी इंटर स्कूल, से एक परीक्षार्थी तुलसी मनी सिंह तथा बालिका इंटर स्कूल,से एक परीक्षार्थी मीना यादव सहित कुल 02 परीक्षार्थी कदाचार में लिप्त पाए गए, जिन्हें परीक्षा से निष्कासित करते हुए नियमानुकूल कार्रवाई की गई है। साथ ही परीक्षार्थियों की फ्रिस्किंग में लापरवाही बरतने से संबंधित वीक्षकों से स्पष्टीकरण की मांग करने का निर्देश दिया गया है।वहीं,परीक्षा के प्रथम पाली में ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, नवादा से ज्योति कुमारी कदाचार में लिप्त पाई गईं, जिन्हें परीक्षा से निष्कासित करते हुए नियमानुकूल कार्रवाई की गई। जिला नियंत्रण कक्ष,नवादा से प्राप्त सूचना के अनुसार जिले के सभी परीक्षा केन्द्रों पर प्रथम एवं द्वितीय पाली की परीक्षा शांतिपूर्ण, स्वच्छ एवं कदाचार-मुक्त वातावरण में सम्पन्न हुई है। प्रथम पाली में गणित विषय की परीक्षा आयोजित की गई, जबकि द्वितीय पाली में राजनीतिक विज्ञान एवं फाउंडेशन कोर्स की परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा का संचालन दो पालियों में किया जा रहा है, जिसमें प्रथम पाली की परीक्षा पूर्वाह्न 9:30 बजे से 12:45 बजे तक तथा द्वितीय पाली की परीक्षा अपराह्न 2:00 बजे से 5:15 बजे तक आयोजित की जा रही है।

राजस्व कर्मी को 35 हजार रिश्वत लेते निगरानी टीम ने दबोचा

केटी न्यूज/नवादा

बिहार निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में मंगलवार को निगरानी की टीम ने नवादा जिले के रोह अंचल कार्यालय में तैनात राजस्व कर्मचारी गुलशन कुमार को 35 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। निगरानी डीएसपी विकास श्रीवास्तव ने बताया कि निगरानी विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि रोह अंचल में तैनात राजस्व कर्मचारी गुलशन कुमार जमीन संबंधी कार्यों के निष्पादन के बदले मोटी रकम की मांग कर रहे हैं। शिकायत के सत्यापन के बाद निगरानी की विशेष टीम ने नवादा में जाल बिछाया। जैसे ही शिकायतकर्ता ने कर्मचारी को 35 हजार रुपये की पहली किस्त थमाई, पहले से तैनात निगरानी की टीम ने

गुलशन कुमार को धर दबोचा। उन्होंने बताया कि आरोपी कर्मचारी गुलशन कुमार को गिरफ्तार करने के बाद टीम उसे पटना ले जायेगी। गिरफ्तारी के दौरान टीम ने वैज्ञानिक तरीके से रंगे हाथों पकड़ने के लिए केमिकल लगे नोटों का इस्तेमाल किया था, जिससे अपराध पूरी तरह साबित हो सके। अब आरोपी से कड़ी पूछताछ की जाएगी, ताकि इस रिश्वतखोरी के सिंडिकेट में शामिल अन्य चेहरों को बेनकाब किया जा सके। निगरानी विभाग ने जनता से अपील की है कि अगर कोई भी अधिकारी काम के बदले रिश्वत मांगता है, तो बेझिझक विभाग को सूचित करें। मिली जानकारी के अनुसार, राजस्व कर्मचारी द्वारा एक व्यक्ति से उसकी जमीन के काम (संभवतः दाखिल-खारिज या जमीन का रसीद काटने) के बदले अवैध रूप से पैसों की मांग की जा रही थी। पीड़ित ने जब इसकी शिकायत पटना स्थित निगरानी ब्यूरो से की, तो विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई का खाका तैयार किया। कर्मचारी के पास से बरामद रिश्वत की राशि को साक्ष्य के तौर पर जब्त कर लिया गया है। निगरानी की इस कार्रवाई से रोह अंचल कार्यालय में हड़कंप मच गया है। बताते चलें कि नवादा में पिछले एक महीने में निगरानी की यह दूसरी कार्रवाई है। इसके पूर्व 2 जनवरी 2026 को अकबरपुर थाने के एक दारोगा को घूस लेते ट्रैप किया गया था।

उन्मुखीकरण और पंजीकरण पत्र वितरण समारोह का आयोजन

केटी न्यूज/आरा

जिला पदाधिकारी तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में पंजीकृत 19 जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समितियों का एक दिवसीय उन्मुखीकरण सह पंजीकरण पत्र वितरण समारोह समाहरणालय सभागार में आयोजित किया गया। इस अवसर पर आयोजित उन्मुखीकरण कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने कहा कि जीविका के संकुल स्तरीय संघों के पंजीकरण के पश्चात समूह की दीदियों को आत्मनिर्भर बनने के अधिक अवसर प्राप्त होंगे तथा वे समाज में अपनी एक अलग पहचान स्थापित कर

सकेंगी। उन्होंने बताया कि जीविका के कुल 38 संकुल स्तरीय संघों में से प्रथम चरण में 12 संघों का पंजीकरण किया गया था तथा आज 19 और संघों के पंजीकरण के साथ कुल 31 संकुल स्तरीय संघों का पंजीकरण सहकारिता विभाग द्वारा पूर्ण किया गया। इस अवसर पर जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहायक निबंधक पदाधिकारी, जीविका जिला परियोजना प्रबंधक बरुण कुमार,पंजीकृत संकुल स्तरीय संघों के पदधारी एवं जीविका के विषयगत प्रबंधक उपस्थित रहें।

एक नजर

छेड़छाड़ कांड का आरोपी गिरफ्तार

बिक्रमगंज। छेड़छाड़ मामले में पुलिस ने एक प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस संदर्भ में थानाध्यक्ष ललन कुमार ने बताया कि नगर परिषद बिक्रमगंज वार्ड संख्या 26 निवासी चंदन यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध स्थानीय थाना में कांड संख्या 850/25 के आलोक में छेड़छाड़ का मामला दर्ज था।

पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार

बिक्रमगंज। सूर्यपुरा पुलिस ने न्यायालय से प्राप्त इश्तेहार को थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अलीगंज निवासी शंकर चौधरी एवं जगनारायण सिंह और ग्राम चौरासी मठिया निवासी छोटन गिरी के घर चिपकाया। इसकी जानकारी थानाध्यक्ष चंदन कुमार भगत ने दी।

रालोमो पार्टी के नवनियुक्त सदस्यों के प्रति कार्यकर्ताओं में हर्ष

नासरीगंज । राष्ट्रीय लोक मोर्चा बिहार प्रदेश किसान प्रकोष्ठ प्रदेश महासचिव गुड्डू उपाध्याय ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सभी नवनियुक्त पदाधिकारी को शुभकामना देते हुए कहा कि जननायक उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में बिहार फर्स्ट बिहार फर्स्ट के उद्देश्य से संगठन को मजबूत करने हेतु नियुक्ति की गई है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर मदन चौधरी को जिम्मेवारी मिली है जिससे पूरे देश में हम मजबूत होंगे हमारी पार्टी मजबूत होगी तो वही दिनारा विधायक आलोक कुमार सिंह को बिहार प्रदेश अध्यक्ष बना करके बिहार पार्टी को मजबूत करने का काम केंद्रीय नेतृत्व किया है साथ ही साथ करणी अध्यक्ष प्रशांत पंकज सुभाष चंद्रवंशी एवं प्रदेश प्रधान महासचिव हिमांशु पटेल का जिमवारी मिला है किसके लिए केंद्रीय नेतृत्व एवं प्रदेश नेतृत्व को बहुत-बहुत धन्यवाद इन सभी नेताओं के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोक मोर्चा आगे बढ़ेगा तथा संगठन मजबूत होगा ऐसा विश्वास है।

महापौर ने पीसीसी सड़क और नाली निर्माण कार्य का किया उद्घाटन

आरा। नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या-20 एवं 43 में पीसीसी सड़क एवं नाली निर्माण कार्य का उद्घाटन महापौर इंदु देवी द्वारा किया गया। मौके पर महापौर इंदू देवी ने कहा कि नगर निगम द्वारा विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। आगे भी जनहित में ऐसे कार्य लगातार किए जाते रहेंगे। उद्घाटन के बाद महापौर ने वहां के स्थानीय नागरिकों से जन समस्या भी सुनी। उसका जल्द से जल्द निवारण करने की आश्वासन दिया। इस दौरान स्थानीय नागरिकों में विशेष उत्साह देखने को मिला। वर्षों से लंबित सड़क एवं नाली निर्माण कार्य पूर्ण होने से क्षेत्रवासियों को आवागमन एवं जल निकासी की समस्या से राहत मिलेगी, जिससे आम जनता में काफी खुशी का माहौल है। कार्यक्रम में वार्ड संख्या-20 की पार्षद राखी कुमारी, पार्षद प्रतिनिधि संतोष पांडेय, वार्ड संख्या 43 के पार्षद श्रीकांत, भाजपा नेता सह कैट भोजपुर के जिलाध्यक्ष आलोक अंजन उर्फ छोटे, भाजयुमो के महामंत्री आदित्य सिंह आदि, सिविल कोर्ट के अधिवक्ता आशुतोष पांडेय, विश्व हिंदू परिषद के राजीव रंजन सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहें। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों की सहभागिता रही, जिनमें प्रमुख रूप से रंगनाथ सिंह, प्रमोद कुमार पांडेय, अमन कुमार, संतोष प्रसाद, विक्की कुमार, भारत प्रसाद, रोहित कुमार, सुमन कुमारी, नीतू कुमारी, अभिलाष सिंह, रितेश कुमार, आजाद श्रीवास्तव, दीपक सिंह, बबलू पांडेय, लवली सिंह, बबलू कुमार, अभिजीत आनंद आदि शामिल थे।

पटना में साइबर ठगी का बड़ा खुलासा : तीन कॉल सेंटरों पर रेड, 22 गिरफ्तार

पटना। आधार कार्ड में सुधार करने के नाम पर पटना के रिहाइशी इलाके में डेढ़ साल से साइबर ठग गिरोह संचालन हो रहा था। आर्थिक अपराध इकाई को इस बात की गुप्त सूचना मिली थी। जिसके बाद साइबर और ईओयू की टीम ने पटना के सगुना मोड़ और रूपसपुर इलाके में अवैध रूप से चल रहे कॉल सेंटर पर छापेमारी की। एक साथ तीन जगहों पर छापेमारी की गयी। इस दौरान 15 महिलाएं और 7 पुरुष को अरेस्ट किया गया। मौके से 19 लैपटॉप, एक डेस्कटॉप, 53 मोबाइल और 12 एटीएम सहित अन्य सामान को जब्त किया गय। इस बड़ी कार्रवाई की जानकारी साइबर डीएसपी संगीता ने दी है। मीडिया से बातचीत करते हुए साइबर डीएसपी ने बताया कि आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा सूचना मिली थी कि सगुना मोड़ और रुपसपुर इलाके में अवैध रूप से कॉल सेंटर चलाया जा रहा है, जिससे साइबर ठगी का काम किया जा रहा है। इस सूचना पर साइबर और आर्थिक अपराधी की टीम अलग-अलग रेड के लिए निकली। तीन लॉकेशन पर रेड किया गया। लखन कुटीर, वेद नगर और सौभाग्य शर्मा पथ में रेड किया गया। तीनों जगहों से 15 महिलाओं और 7 पुरुष को गिरफ्तार किया है। 19 लैपटॉप, एक डेक्सटॉप, 53 मोबाइल, 12 एटीएम सहित अन्य सामान जब्त किया गया है। ये लोग आईआरसीटी से डेटा डाउनलोड करते थे, साइबर कैफे वाले इनके टारगेट होते थे। वहां से डेटा डाउनलोड करते थे और लोगों को कॉल करवाया जाता था। आधार सेंटर के नाम पर लोगों के साथ फ्रॉड किया जा रहा था। लड़कियां कॉल करती थी क्लाइंट्स लाती थी। उसके बाद आगे का काम बाकी लोग करते थे। 8 से 10 हजार रुपये इन लड़कियों को सैलरी दी जा रही थी। डेढ साल से यह गिरोह चल रहा था। यहां बैठकर इन लोगों ने कई लोगों को शिकार बनाकर करोड़ों रुपये की ठगी की है। इनके मुख्य सरगना अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है।

अब बुलेट प्रूफ रेंज रोवर पर चलेंगे नीतीश कुमार, काफिले में नई गाड़ियां होंगी शामिल

एजेंसी। पटना

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले में जल्द ही बुलेटप्रूफ रेंज रोवर शामिल होंगे, जबकि फिलहाल वह हुंडई ईवी कार से सफर करते हैं. आज वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने बिहार का 2026-27 का बजट पेश किया, जो 3.47 लाख करोड़ रुपये का है और राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है. इसमें शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी गई है. बजट को नीतीश सरकार के 'सात निश्चय-3' विजन और पांच संकल्पों पर आधारित रखा गया है, और शिक्षा के लिए रिकॉर्ड 68,216.95 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले में जल्द ही नई गाड़ियां शामिल होने वाली हैं. सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री अब बुलेट प्रूफ रेंज रोवर में सफर करेंगे. राज्य सरकार ने इन गाड़ियों की खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी है. फिलहाल नीतीश कुमार हुंडई ईवी कार से अपनी यात्रा करते हैं, लेकिन नई गाड़ियों के शामिल होने के बाद सुरक्षा और सुविधा दोनों बढ़ जाएंगी.बिहार के वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने मंगलवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया. नीतीश सरकार ने अपने 'सात निश्चय-3' विजन के तहत 3.47 लाख करोड़ रुपये का रोडमैप तैयार किया है, जो पिछले साल के बजट से 30,694.74 करोड़ रुपये अधिक है और राज्य के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है. इस बजट में सरकार ने शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है. वित्त मंत्री का बजट भाषण केवल 11 मिनट का था, जो बिहार विधानसभा में अब तक का सबसे संक्षिप्त बजट भाषण है. उन्होंने कहा कि इस बजट के जरिए 2025 से 2030 तक 1 करोड़ रोजगार सृजन और कृषि रोडमैप-4 के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है. फाइनेंस मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बजट को ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान और सम्मान के पांच संकल्पों पर आधारित रखा है. 'सात निश्चय-3' योजना के जरिए राज्य के विकास को नई गति देने की रणनीति बनाई गई है. महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों की दीदियों को 10,000 रुपये से 2 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता और ऋण देने का प्रावधान किया गया है. सरकार का विजन 'सबका सम्मान, जीवन आसान' के मंत्र के साथ हर वर्ग को मुख्यधारा में जोड़ने का है. बजट में सबसे बड़ी राशि शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए 68,216.95 करोड़ रुपये आवंटित की गई है, जो किसी भी विभाग के लिए अब तक का सबसे बड़ा निवेश।

नीतीश सरकार के पांच संकल्प

फाइनेंस मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बजट को ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान और सम्मान के पांच संकल्पों पर आधारित रखा है. 'सात निश्चय-3' योजना के जरिए राज्य के विकास को नई गति देने की रणनीति बनाई गई है. महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों की दीदियों को 10,000 रुपये से 2 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता और ऋण देने का प्रावधान किया गया है. सरकार का विजन 'सबका सम्मान, जीवन आसान' के मंत्र के साथ हर वर्ग को मुख्यधारा में जोड़ने का है. बजट में सबसे बड़ी राशि शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए 68,216.95 करोड़ रुपये आवंटित की गई है, जो किसी भी विभाग के लिए अब तक का सबसे बड़ा निवेश है।

कला और संस्कृति को बिहार बजट 2026 में मिले पंख, गरीब कलाकारों के लिए 3 हजार की पेंशन

एजेंसी। पटना

बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने दोपहर 2 बजे विधानसभा में बजट प्रस्तुत किया। यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार का चुनाव के बाद पहला पूर्ण बजट है। इस बजट में कला एवं संस्कृति विभाग को लेकर कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की गई, जिससे राज्य में पारंपरिक और आधुनिक कलाओं को बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार ने कला के क्षेत्र में जीवन भर योगदान देने वाले वरिष्ठ, उपेक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों के लिए 'मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना' की शुरूआत की है। इस योजना के तहत पात्र कलाकारों को 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन सहायता

दी जाएगी, ताकि उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिल सके। अब तक पटना, सारण, खगड़िया, कटिहार, पूर्णिया, बांका, भोजपुर, अररिया, जहानाबाद और किशनगंज जिलों के 85 कलाकारों का चयन किया गया है। इस योजना के तहत अनुभवी कलाकारों को 'गुरु' और युवाओं को 'शिष्य' बनाकर पारंपरिक लोक कला, संगीत, नृत्य और वादन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सरकार द्वारा गुरु को 15,000 रुपये, संगतकार को 7,500 रुपये और शिष्य को 3,000 रुपये प्रति माह सहायता दी जा रही है। राज्य सरकार ने सांस्कृतिक गतिविधियों को जिला स्तर पर संस्थागत रूप से बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'अटल कला भवन निर्माण' योजना के तहत प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में 620 दर्शक क्षमता वाले आधुनिक अटल कला भवन का निर्माण शुरू किया है। सारण, गया, पूर्णिया, सहरसा, बेगूसराय, मुंगेर और दरभंगा में निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। लखीसराय और बांका में निर्माण कार्य प्रगति पर है, जबकि नवादा, शेखपुरा, अरवल, बक्सर, कैमूर (भभुआ), सिवान और अररिया में कार्य प्रक्रियाधीन है। वैशाली की ऐतिहासिक भूमि पर 550.48 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित "बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय-सह-स्मृति स्तूप" का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है और इसे आम जनों के लिए सुलभ किया गया है।

बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति, 2024 : इस नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप राज्य में 30 से अधिक फिल्मों, वेब सीरीज और डॉक्यूमेंट्री परियोजनाओं को शूटिंग की अनुमति प्रदान की गई है। फिल्म और नाट्य के क्षेत्र में 20 मेधावी युवाओं को कुल 13.53 लाख रुपये छात्रवृति प्रदान की गई है। इससे बिहार के युवा राष्ट्रीय स्तर की कला शिक्षा प्राप्त कर राज्य की रचनात्मक पहचान को और सशक्त बनाएंगे।

'ज्ञान भारतम' मिशन और पाण्डुलिपि संरक्षण : 'ज्ञान भारतम' मिशन के अंतर्गत पाण्डुलिपि संरक्षण के लिए संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार सरकार के बीच समझौता ज्ञापन किया गया। इस मिशन का उद्देश्य भारत की विशाल पाण्डुलिपि विरासत को संरक्षित, डिजिटाइज और प्रसारित कर भविष्य की पीढ़ियों के लिए ज्ञान को सुलभ बनाना है। बजट में इन पहलों से न केवल कलाकारों और युवाओं को सहारा मिलेगा, बल्कि बिहार की सांस्कृतिक धरोहर और पारंपरिक कला को संरक्षित करने में भी महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।

अटल कला भवन निर्माण योजना

राज्य सरकार ने सांस्कृतिक गतिविधियों को जिला स्तर पर संस्थागत रूप से बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'अटल कला भवन निर्माण' योजना के तहत प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में 620 दर्शक क्षमता वाले आधुनिक अटल कला भवन का निर्माण शुरू किया है। सारण, गया, पूर्णिया, सहरसा, बेगूसराय, मुंगेर और दरभंगा में निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। लखीसराय और बांका में निर्माण कार्य प्रगति पर है, जबकि नवादा, शेखपुरा, अरवल, बक्सर, कैमूर (भभुआ), सिवान और अररिया में कार्य प्रक्रियाधीन है।

एक नजर

लाल सूटकेस में महिला का शव मिलने का खुलासा, पति निकला कातिल

कैमूर। पत्नी की हत्या कर फरार पति को पुलिस ने 48 घंटे बाद गिरफ्तार किया है। पत्नी की लाश लाल सूटकेस में बंद कर डेहरी रेलवे स्टेशन के पास कचरे में ढेर में फेंक कर पति फरार हो गया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले का खुलासा किया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। कैमूर जिले के सोनहन थाने की पुलिस ने रोहतास जिले की डेहरी में पत्नी की हत्या कर फरार एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कयामुद्दीन शेख मंसूरी, निवासी जक्की बिगहा गांव (डीहरी थाना क्षेत्र), रोहतास जिला है। उसने एक फरवरी 2026 को अपनी पत्नी की हत्या की और शव को लाल सूटकेस में बंद कर डेहरी रेलवे स्टेशन के पास कचरे के ढेर में फेंक दिया था। इसके बाद वह फरार हो गया था। मृतका के परिजनों ने शुरू से ही पति पर हत्या का आरोप लगाया था। रोहतास पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए आरोपी कैमूर जिले के रास्ते वाहन में छिपकर भाग रहा था। सोनहन पुलिस द्वारा बेलांव मोड़ पर चलाए जा रहे वाहन जांच अभियान के दौरान संदिग्ध व्यक्ति चार पहिया वाहन से कूदकर भागने लगा। पुलिस ने दौड़कर उसे पकड़ा। पूछताछ में वह बार-बार गलत नाम-पता बताता रहा, लेकिन सख्ती पर उसने अपनी असली पहचान कयामुद्दीन मंसूरी बताई और पत्नी हत्या की वारदात कबूल की।

पुजारी हत्याकांड! में बड़ा फैसला, दो महिला समेत 3 दोषियों को उम्रकैद की सजा

गोपालगंज । गोपालगंज में करीब दो साल पुराना चर्चित पुजारी हत्याकांड में अदालत का अहम फैसला सामने आया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-क की अदालत ने इस सनसनीखेज मामले में दो महिलाओं समेत तीन अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। जुमार्ना अदा नहीं करने पर दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी। यह पूरा मामला दानापुर गांव, थाना मांझा थाना क्षेत्र का है। बीते दिसंबर 2023 में गांव के एक पुजारी की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई थी। शुरूआत में यह मामला गुमशुदगी और रहस्यमय हालात से जुड़ा लगा, लेकिन जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, कहानी ने सनसनीखेज मोड़ ले लिया। सामने आया कि इस वारदात के पीछे प्रेम प्रसंग, साजिश और सबूत छिपाने की सुनियोजित कोशिश शामिल थी। पुलिस अनुसंधान में खुलासा हुआ कि पुजारी का एक महिला के साथ प्रेम संबंध था। इसी संबंध को लेकर विवाद और तनाव बढ़ा। आरोप है कि महिला ने सुनियोजित तरीके से पुजारी की हत्या की और शव को छिपाने की कोशिश की। हत्या के बाद शव को घर के हौदी/टंकी जैसे स्थान में करीब तीन दिनों तक छिपाकर रखा गया, ताकि किसी को भनक न लगे।

रेलवे फाटक बंद रहने से भड़के लोग, कार्यालय में तोड़फोड़ और गेटमैन के साथ की मारपीट

समस्तीपुर। पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर- खगड़िया रेलखंड के समस्तीपुर भगवानपुर देसुआ रेलवे स्टेशन के बीच जितवारपुर चौथ गांव के पास स्थित रेलवे फाटक संख्या 40 सी पर मंगलवार को लोगों ने तोड़फोड़ की। इस दौरान गेटमैन के साथ मारपीट भी की गई। आक्रोशित लोग इंटर परीक्षार्थी के अभिभावक बताए जा रहे हैं। मारपीट की घटना के बाद आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि रेलवे फाटक बंद था। इंटर परीक्षा की दूसरी पाली में शामिल होने के लिए विभिन्न वाहनों से परीक्षा केदों पर जा रहे थे। लेकिन गेट बंद रहने के कारण बड़ी संख्या में लोग गेट पर रुके हुए थे ।काफी देर बीत जाने के बावजूद गेट जब नहीं खोला गया तो गेट के दोनों तरफ फंसे लोग आक्रोशित हो उठे। पहले लोगों ने गाली गलौज शुरू की फिर देखते-देखते माहौल गर्म हो गया। और लोगों ने रेलवे फाटक में तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस दौरान रेलवे उपस्कर के साथ ही टेलीफोन डायरी तार आदि को तोड़ डाला गया। वहीं प्रतिरोध करने पर गेटमैन के साथ मारपीट भी की गई।

बार-बार नियम तोड़ने वालों पर सख्ती : 52 हजार ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन/रद्द करने का निर्देश

एजेंसी। पटना

राज्य परिवहन आयुक्त आरिफ अहसन ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, मोटरयान निरीक्षक, ईएसआई एवं आरटीए सचिवों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रस्तावित कैशलेस उपचार योजना, आरसी एवं डीएल पेंडेंसी, पीएम ई-ड्राइव चार्जिंग स्टेशन, परमिट पेंडेंसी, हेलमेट एवं सीटबेल्ट जांच इत्यादि की समीक्षा की गई। राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से श्री अहसन ने मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं का कड़ाई से अनुपालन कराने पर बल दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि बार-बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन अथवा रद्दीकरण

की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। लाइसेंस निलंबन/रद्दीकरण से संबंधित प्राप्त सूचियों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे वाहनों के वाहन निबंधन संख्या को अखबारों में प्रकाशित कराते हुए नोटिस निर्गत किया जाए तथा विधिसम्मत सुनवाई के उपरांत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। पुलिस एवं यातायात से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर लगभग 52 हजार मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन/रद्द करने की कार्रवाई की जानी है। इसमें पटना, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर जिलों में सर्वाधिक मामलों की सूची प्राप्त हुई है। बैठक में श्री अहसन ने सबका सम्मानः जीवन आसान (Ease of Living) सात निश्चय-3 के तहत परिवहन सेवाओं को आम जनता तक समयबद्ध एवं निर्बाध रूप से पहुँचाने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि परिवहन सेवाओं में किसी भी प्रकार का विलंब बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होगा।

पटना में स्नातक पैरामेडिकल छात्रों का प्रदर्शन, स्टाइपेंड व कैडर गठन की उठी मांग

एजेंसी। पटना

राजधानी पटना में मंगलवार को स्नातक पैरामेडिकल छात्र संघ के दर्जनों छात्र अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए। छात्रों ने करगिल चौक से अशोक राजपथ तक मार्च करते हुए बिहार लोक स्वास्थ्य संस्थान के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि राज्य के स्नातक पैरामेडिकल छात्रों के साथ लगातार उपेक्षा की जा रही है। छात्रों ने मांग की कि सभी स्नातक पैरामेडिकल छात्रों को 20,000 प्रति माह की इंटर्नशिप स्टाइपेंड तत्काल लागू की जाए, ताकि प्रशिक्षण अवधि के दौरान उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। छात्र संघ ने यह भी मांग रखी कि राज्य में जल्द से जल्द एक अलग पैरामेडिकल कैडर का गठन किया जाए और राज्य स्तरीय काउंसलिंग व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी और सुचारू रूप से

लागू किया जाए, जिससे छात्रों को रोजगार और नियुक्ति में किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसके अलावा छात्रों ने बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षाएं और परिणाम समय पर जारी नहीं किए जा रहे हैं, जिससे छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। मौके पर प्रशासन और पुलिस बल तैनात रहा, हालांकि प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ।

बेतिया में एक साथ एक ही गांव की पांच नाबालिग लड़कियां लापता, जांच में जुटी पुलिस

एजेंसी। पटना

बेतिया जिले के नरकटियागंज अनुमंडल के कुमारबाग थाना क्षेत्र के लखौरा गांव के एक ही मोहल्ले की पांच नाबालिग लड़कियां अचानक लापता हो गई हैं। इस घटना के बाद पूरे गांव में दहशत और बेचैनी का माहौल व्याप्त है ।लापता लड़कियों की पहचान मुनमुन कुमारी (17 वर्ष), पिता रघुचन साह, काजल कुमारी (16 वर्ष), पिता रुदल साह, रामानती कुमारी (14 वर्ष), पिता प्रह्लाद साह, निगम कुमारी (15 वर्ष), पिता सोनू साह और निपु कुमारी (14 वर्ष), पिता शिव साह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि पांचों लड़कियां दिन के समय अपने-अपने घरों से निकली थीं। कुछ ने सिलाई सीखने का बहाना बनाया, जबकि कुछ खेत जाने की बात कहकर घर से बाहर गईं। परिजनों को किसी भी तरह का अंदेशा नहीं था कि बेटियां अचानक गायब हो जाएंगी।

जब देर शाम तक लड़कियां घर नहीं लौटीं, तो परिजनों ने पहले खुद उन्हें ढूंढा, फिर रिश्तेदारों और आसपास के गांवों में खोजबीन की। किसी भी सुराग के न मिलने पर उन्होंने कुमारबाग थाना में शिकायत दर्ज कराई ।घटना के बाद लखौरा गांव में सन्नाटा छा गया है। परिजन बदहवास हैं और रो-रोकर अपनी बेटियों की तलाश कर रहे हैं। कई परिजन अपनी बेटियों की तस्वीरें लेकर पुलिस से मदद की गुहार लगा रहे हैं। ग्रामीण भी इस घटना से गहरे सदमे में हैं और किसी अनहोनी की आशंका जता रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए कुमारबाग पुलिस ने [illegible] दर्ज कर कई टीमें बनाकर खोजबीन शुरू कर दी है। पुलिस रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और प्रमुख चौक-चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि किसी सुराग तक पहुंचा जा सके।

बिहार के 19 जिलों में घना कोहरा, छपरा में दृश्यता 50 मीटर से कम, बारिश का अलर्ट

एजेंसी। पटना

बिहार के 19 जिलों में सोमवार को घना कोहरा छाया रहा, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सुबह के समय सड़कों, रेलवे ट्रैक और हवाई सेवाओं पर कोहरे का खास असर देखने को मिला। सबसे ज्यादा परेशानी छपरा में दर्ज की गई, जहां दृश्यता घटकर 50 मीटर से भी कम हो गई। घने कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार थम सी गई और लोगों को ऑफिस, स्कूल और अन्य जरूरी कामों पर पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, राज्य में ठंड का असर अभी पूरी तरह कम नहीं हुआ है

और आने वाले कुछ दिनों तक सुबह के समय कोहरा छाए रहने की संभावना बनी हुई है। विभाग ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बिहार के कुछ हिस्सों में मौसम में बदलाव देखा जा सकता है। खासकर दक्षिण-पश्चिमी जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने रोहतास और कैमूर जिलों के लिए हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में बादल छाए रहने और बूंदाबांदी की संभावना है, जिससे तापमान में और गिरावट हो सकती है। बारिश के चलते खेतों में खड़ी फसलों पर भी असर पड़ सकता है, हालांकि हल्की बारिश रबी फसलों के लिए कुछ हद तक लाभकारी भी मानी जा रही है। घने कोहरे का असर रेल और हवाई सेवाओं पर भी पड़ा है। कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं, जबकि कुछ ट्रेनों को रद्द भी करना पड़ा है। पटना एयरपोर्ट पर भी कोहरे के कारण उड़ानों के संचालन में बाधा आई है। यात्रियों को घंटों तक इंतजार करना पड़ा, जिससे लोगों में नाराजगी देखी गई। प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे सफर से पहले मौसम की जानकारी जरूर लें और सावधानी बरतें। सड़कों पर दृश्यता कम होने के कारण सड़क दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है। ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से धीमी गति से चलने, फॉग लाइट का उपयोग करने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है। खासकर राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत बताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 24 से 48 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में कोहरा छाया रह सकता है, जबकि कुछ जिलों में बादल और हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। तापमान में फिलहाल कोई बड़ी बढ़ोतरी के आसार नहीं हैं, जिससे ठंड का असर बना रहेगा। बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। कुल मिलाकर, बिहार में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। घने कोहरे और संभावित बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया है। आने वाले दिनों में भी मौसम में उतार-चढ़ाव जारी रहने की संभावना है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने और मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने की आवश्यकता है।

शिवहर में डकैती कांड का खुलासा : लूटे गये सामान के साथ दो अपराधी गिरफ्तार

एजेंसी। पटना

शिवहर के सदर थाना क्षेत्र में हुई डकैती कांड का पुलिस ने उद्भेदन किया है। लूटे गये सामान के साथ दो बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस इसे बड़ी सफलता मान रही है। बता दें कि सुंदरपुर खरौना निवासी बिंदेश्वरी राय के घर 29 जनवरी को डकैती हुई थी। इस घटना का शिवहर पुलिस ने सफल उद्भेदन करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस डकैती की घटना को 5झ6 अज्ञात अपराधियों द्वारा अंजाम दिया गया था। पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा ने मंगलवार को एसपी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान इस कांड का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि घटना में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुशील कुमार के नेतृत्व में विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया था. एसआईटी ने तकनीकी साक्ष्यों, घटनास्थल से प्राप्त भौतिक साक्ष्यों, गहन अनुसंधान एवं गुप्त सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई करते हुए इस कांड में संलिप्त दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार अपराधियों की पहचान तरियानी थाना क्षेत्र के कस्तुरिया गांव निवासी आलमगीर उर्फ माइकल एवं नास आलम के रूप में हुई है।